ISSN 2278-8808
An International Peer Reviewed
SCHOLARLY RESEARCH JOURNAL
FOR INTERDISCIPLINARY STUDIES

आतंकवाद की उभरती चुनौतियाँ
(भारतीय सुरक्षा के सन्दर्भ में)

हेमन्त कुमार पाण्डेय, Ph. D.
सह–आचार्य, रक्षा अध्ययन विभाग, मेरठ कॉलेज, मेरठ
मौ0 मरगूब
पी जी, छात्र रक्षा अध्ययन विभाग, मेरठ कॉलेज, मेरठ

आतंकवाद आज एक ऐसी उभरती वैश्विक चुनौती है, जिसने पूरे विश्व को अपनी खूनी जद में ले लिया और भारत भी इसका अपवाद नहीं है। 9/11 की घटना से पहले भी भारत में आतंकी वारदातें होती रही पर ज्यादातर आतंकी हमले जम्मू–कश्मीर या पंजाब में हुआ करते थे लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इन घटनाओं में निरंतर बढ़ोतरी हुई है। यह भारत का दुर्भाग्य है कि भारत में उत्तर, दक्षिण या फिर पूरब और पश्चिम हर सीमान्त पर असंतुष्ट तत्वों ने अपनी मांगों के लिए आतंकवाद का ही रास्ता चुना और हमारे पड़ौसी देश के क्रियाकलापों से उन्हें काफी बल मिला। दरअसल आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले संगठनों का एक ही मकसद है कि लोगों में आपसी अविश्वास बूढ़े, विविध धर्म और सम्प्रदायों के बीच की खाई गहरी हो और किसी भी तरह विकास अवरूद्ध हो इसलिए कभी गुजरात के अक्षरधाम मंदिर पर हमले किए गए तो कभी महाराष्ट्र की मस्जिद में कभी मुम्बाई के झावेरी बाजार में बम विस्फोट किए गए तो कभी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हाईकोर्ट के पास बम विस्फोट किए गए। इतना ही नहीं आतंकियों ने भारतीय लोकतंत्र के प्रतीक संसद पर हमले करके यह दिखाया है कि उनके मंसूबे कितने खतरनाक है।

हम भारत के लोगों को यह याद दिलानें की जरूरत कतई नहीं है कि ऐसे आतंकवादी संगठनों को पाकिस्तान से लेकर सूडान तक कई देशों द्वारा संरक्षण मिल रहा है। लेकिन हमें यह भी याद रखना होगा कि संगठन केवल वही नहीं फलत–फूलते है, जहाँ की सरकार उन्हें सक्रिय मदद देती है। उनके लिए तो जिस देश की सरकार कमजोर पड़ जाती है, उसी की सरजमी इनके लिए उपयोगी साबित होती है। हमारे पड़ोस में तो ऐसे क्षेत्रों की भरमार है– बँगलादेश, म्यांमार, भूटान और नेपाल के विशाल भू–भाग है। जैसे बांग्लादेश को ही ले बांग्लादेश का पाकिस्तान और चीन के साथ संबंध तथा स्वयं बांग्लादेश में शासन की ढ़ाँचागत कमजोरी भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है। इसी प्रकार नेपाल,

श्रीलंका आदि हमारे पड़ोसी देशों की सरकार अपने यहाँ के आतंकी संगठनों को कुचलने में अक्षम है, जिसका खामियाजा भारत को भुगतना पड़ रहा है।

दुनियाभर में आतंकवाद की घटनाएँ बढ़ रही है और भारत भी इसका अपवाद नहीं है। 9/11 की घटना से पहले भी भारत से आतंकी वारदातें होती रही पर पहले ज्यादातर आतंकी हमले जम्मू–कश्मीर या पंजाब में हुआ करते थे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इन घटनाओं में तो बढ़ोतरी हुई ही है, देश के अन्य हिस्से भी निशाना बने हैं। इससे एक बात यह साफ हो गयी है कि भारत में अल–कायदा जैसे खतरनाक आतंकी संगठन का नेटवर्क बढ़ रहा है।

दरअसल आतंकवाद के बढ़ावा देने वाले संगठनों का एक ही मकसद है कि लोगों में आपसी अविश्वास बढ़े, विविध धर्म और सम्प्रदायों के बीच की खाई गहरी हो और किसी भी तरह विकास अवरूद्ध हो इसलिए कभी गुजरात के अक्षरधाम मंदिर पर हमले किए गए तो कभी महाराष्ट्र की मस्जिद में। इतना ही नहीं आतंकियों ने संसद पर हमला करके यह दिखाया है कि उनके मंसूबे कितने खतरनाक हैं।

इस बात में कोई दो राय नहीं है कि भारत में सक्रिय अलकायदा, जैश–ए–मोहम्मद और लश्कर–ए–तैयबा जैसे आतंकी सगठनों को पाकिस्तान के साथ–साथ बांग्लादेश ओर नेपाल के स्थानीय आतंकी संगठनों से भी पूरी–पूरी मदद मिलती है। पड़ोसी मुल्कों के अलावा भारत में सक्रिय अलगाववादी गुट भी इन आतंकी संगठनों की सहायता करते है। अपनी ही धरती पर मिल रहे इस समर्थन से आतंकवादी कामयाब भी होते दिखाई दे रहे हैं। एक बात हो साफ है कि इन अन्तर्राष्ट्रीय किस्म के आतंकवादी संगठनों द्वारा अब भारत में सिलसिलेवार बम विस्फोटों को अंजाम दिया जा रहा है।

इस बात की पुष्टि पाकिस्तान की आई एस आई, लश्कर–ए–तय्यबा (एलईटी) और हूजी जैसे गिरोहों द्वारा तैयार किए गए 'कराची प्रोजेक्ट' के तहत, पाकिस्तान में स्थानीय स्तर पर उपलब्ध बम समाग्री का इस्तेमाल किया जाए ऐसी योजना का दोहरा उद्देश्य था– पाकिस्तान का हाथ होने का संदेह पैदा किए बिना भारत के अंदरूनी हिस्से में आतंकवादी हमले करना क्योंकि 26/11 के मुंबई हमले जिसमें पाकिस्तान के नागरिक अजमल आमिर कसाब के रूप में पाकिस्तान का हाथ होने का जीता–जागता सबूत मिल गया था, के विपरीत इस अभियान में सिर्फ भारतीयों का इस्तेमाल किया जाना था। इन युवाओं को लश्कर के लोगों ने भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में भर्ती किया था।

कराची प्रोजेक्ट के तहत किए गए हमलें–

- 28 जुलाई 2005– पटना–नई दिल्ली ट्रेन में आइईडी की वजह से 10 यात्रियों की मौत और 79 घायल।
- 29 अक्टूबर 2005– दीवाली से पहले एक के बाद एक बम धमाको में 62 लोग मौत के मुँह में समा गए।

- 7 मार्च 2006– वाराणासी के संकट मोचन मंदिर और रेलवे स्टेशन पर तीन विस्फोटों में 21 लोग मारे गए।
- 11 जुलाई 2006– मुम्बई में छः लोकल ट्रेनों में भारी भीड़ वाले समय हुए सात विस्फोट जिसमें 209 लोग मारे गए।
- 25 अगस्त 2007– हैदराबाद में एक गार्डन और अल्पाहार स्टाल में हुए विस्फोट में 42 लोगों की मौत।
- 24 नवम्बर 2007– लखनऊ, वाराणसी, फैजाबाद तीन शहरों के अदालत परिसर में विस्फोटों ने 16 जाने ले लीं।
- 13 मई 2008– जयपुर, बाजार में नौ विस्फोटों में 63 लोगों की जान गई।
- 26 जुलाई 2008– अहमदाबाद, 17 स्थानों पर हुए 22 विस्फोटों में 53 लोग मौत मे मुँह में समा गए।
- 13 सितम्बर 2008– दिल्ली, विभिन्न स्थानों पर हुए पांच विस्फोटों में 30 लोग मारे गए।
- 13 फरवरी 2010– पुणे, एक रेस्तरां में विस्फोट 11 जाने ले ली।

इसी तरह आतंकवादियों द्वारा अपनी खूनी करतूत का एक और बड़ा कारनामा तब सामने आया जब मुम्बई के 150 साल पुराने झवेरी बाजार में 13 जुलाई को शाम 6:54 बजे मोटरसाईकिल में रखे एक बम के विस्फोट से पांच लोगों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया इस विस्फोट के एक मिनट बाद ही शाम 6:55 बजे ऑपेरा हाउस के प्रसाद चेंचर्स में एक टिफिन बाक्स में जोरदार विस्फोट हुआ इसमें नौ लोगों की मौत हो गई। इसी के बाद एक तीसरा विस्फोट कबूतरखाना इलाके के पास किया गया। पुलिस आयुक्त ने बताया कि धमाकों के लिए चुने गए समय ओर तरीके संगठन इंडियन मुजाहिदीन (आइ एम) की आर इशरा करते है। इससे पहले 11 जुलाई 2006 को लोकल ट्रेन में हुए विस्फोटो के पीछे भी आइ एम का ही हाथ बताया जाता है इन दोनों ही हमलों में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया, ये विस्फोट भी शाम 6:30 बजे से 7:00 बजे के बीच हुए थे लगता है शायद एजेंसिया किसी मुगालते का शिकार हो गई थी 26/11 के बाद 13 फरवरी 2010 को पुणे की जर्मन बेकरी में बड़ा हमला हुआ था जिसमें 17 लोगों की मौत हो गई थी और इसके पीछे भी आई एम का हाथ माना गया था विश्लेषकों का मानना है कि पाकिस्तान की समस्याओं की वजह से हमलों में कमी आई थी लगता है, पड़ोसी मुल्क अपनी परेशानियों में उलझने की वजह से भारत के भीतर आतंकी हमलों के लिए नहीं उकसा पा रहा था। एक अधिकारी मानते है कि आई बी का मल्टी एजेंसी सेंटर जिसे 26/11 के हमलों के बाद देश की 14 एजेंसियों को हर रोज सूचनाएं साझा करने के लिए बैठक करने को कहा था– ने साइबर वर्ल्ड में वर्चुअल हमलों पर बातचीत पर ध्यान केंद्रित कर दिया था। 26/11 के बाद सब तरह ध्यान भटक गया था। नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड जैसे आतंकवाद संबंधी महत्वपूर्ण प्रस्तावों को केन्द्र में काफी प्रतिरोध झेलना पड़ा गृह मंत्रालय ने संदिग्ध आतंकियों पर नजर

रखने के लिए बैंक खाते और वित्तीय लेन–देन जैसे प्रशिक्षिण भारतीय आतंकवादियों का इस्तेमाल भारत के चुनिंदा शहरों में विस्फोटक लगाने के लिए किया जा रहा है, से हो जाती है।

सन् 2003 में आई एस आई, पाक सेना, लश्कर और हूजी द्वारा के साझी रणनीति के तहत करांची में शरण दिए गए, भगोड़ों का इस्तेमाल भारतीय युवाओं को बांग्लादेश और नेपाल के जरिए पाकिस्तान लाकर हथियारों और विस्फोटकों का प्रशिक्षण देना है जहाँ उन्हें बाबरी मस्जिद और गुजरात दंगों के वीडियों दिखाकर आतंकवाद की दीक्षा दी जाती है। रियाज और इकबाल भटकल जैसे माफिया सरगना और भगोड़ों का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने के लिए भारत से युवाओं की भर्ती जारी रखने के लिए किया जाता है। आतंकवादी गतिविधियों में भारतीयों के इस्तेमाल से पाकिस्तान को सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि इन आतंकी घटनाओं में अपना हाथ न होने का दावा करने लगता है।

अपराधों की राजधानी और दाऊद इब्राहिम तथा टाइगर मेमन जैसे माफिया सरगना और भगोड़ों की पनाहगाह बन चुके पाकिस्तान के इस बंदरगाह शहर के नाम पर इस षड्यंत्र का नामकरण किया गया– 'कराची प्रोजेक्ट' कराची प्रोजेक्ट ही 2005 के बाद से भारत में हुए 10 विस्फोटो और उनमें हुई 500 मौतों के लिए जिम्मेदार है। इस प्रोजेक्ट का ब्यौरा पहली बार पाकिस्तान में जन्में अमेरिकी जिहादी डेविड कोलमैन हेडली ने पिछले साल दिसम्बर में एफ बी आई को दिया था। हेडली ने पुष्टि की कि आई एस आई ने भारतीय जिहादियों के एक दल को कराची में एकजुट किया था और इसे कराची प्रोजेक्ट नाम दिया। हेडली ने ही 2006 और 2008 के चीन मुम्बई और कराची आते जाते हुए 26/11 के मुम्बई हमलों के लिए निशाने पर चुनाव किया था।

इस योजना का अधिक विस्तृत ब्यौरा शाहिद बिलाल के सेकेंड–इन–कमांड अब्दुल ख्वाजा की गिरफ्तारी के बाद सामने आया ख्वाजा हूजी की बांग्लादेश इकाई का अध्यक्ष था, जिसे बांग्लादेश में एक गुप्त अभियान में रॉ ने गिरफ्तार किया। आतंकवादियों के इस खतरनाक गठजोड़ के आयाम एकदम सरल थे कि आतंकवादी हमले करने के लिए देश से द्रोह अथवा द्वेष भाव रखने वाले भारतीय युवाओं का इस्तेमाल किया जाए, हमले के लिए मौजूदा डाटाबेस को समेकित करने की परियोजना बनाई थी। इस परियोजना को 18 महीने बाद ही सशर्त मंजूरी मिली थी।

इसमें, मुम्बई की अंतर्निहित कमजोरी को और जोड़ दीजिए, जिससे यह आसान निशाना बन जाती है। जैसे लंबाई में 468 वर्ग किमी, में बसे इस शहर का आकार 1,483 वर्ग किमी. वाली दिल्ली के मुकाबले एक–तिहाई है। लेकिन यह देश की सबसे ज्यादा घनी आबादी वाला शहर है। दिल्ली में प्रति वर्ग किमी. में 9,294 लोग रहते है जबकि मुंबई में इतने ही इलाके में 29,042 लोग रहते हैं। जिसकी वजह से उसके 60,000 पुलिस वालों के लिए सबकी निगरानी करना मुश्किल हो जाता है। उसके तट हमले के लिए खुले हैं, जैसा कि 26/11 ने साबित कर दिया था।

एक बात तो तय लगती है कि पिछले कई वर्षों से हुए आतंकी हमलों को देखते हुए कह सकते है कि इन आतंकियों के लिए भारत में विस्फोट करना कितना आसान है और ये आतंकी साफ बच कर निकल भी जाते है, इसकी पुष्टि निम्न तालिका से हो जाती हैः–

आतंकी हमला	जांच एजेंसी	स्थिति
मुंबई सीरियल बलास्ट 13 जुलाई 2011	एटीएस, मुंबई राज्य सरकार के अधीन	कोई गिरफ्तारी नहीं अनसुलझा।
दिल्ली हाइकोर्ट 25 मई, 2021 मृत कोई नहीं	स्पेशल सेल, दिल्ली पुलिस केन्द्रीय गृह मंत्रालय के अधीन	कोई गिरफ्तारी नहीं अनसुलझा।
शीतला घाट, वाराणसी 7 दिसंबर, 2010	एटीएस, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के अधीन	कोई गिरफ्तारी नहीं अनसुलझा।
जामा मस्जिद, दिल्ली 9 दिसंबर 2010, मृत कोई नहीं, घायल–2	स्पेशल सेल, दिल्ली पुलिस केन्द्रीय गृह मंत्रालय के अधीन	कोई गिरफ्तारी नहीं अनसुलझा।
चिन्नास्वामी स्टेडियम, बंगलुरू 4 अप्रैल, 2010, मृत कोई नहीं, घायल–17	क्राइम ब्रांच बंगलुरू पुलिस राज्य सरकार के अधीन	कोई गिरफ्तारी नहीं अनसुलझा।
जर्मन बेकरी, पुणे 13 फरवरी, 2010, मृत 17, घायल 56	एटीएस, मुंबई राज्य सरकार के अधीन	7 अभियुक्त, 1 गिरफ्तारी आरोप पत्र दाखिल।

स्त्रोतः गृह मंत्रालय, 8 अगस्त, 2011 तक

अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद से लड़ने के तौर–तरीकों की कमजोरी

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पिछले दिनों आतंकवाद के मसले पर विचार करने के लिए मुख्यमंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित किया। उन्होने सम्भावित स्थितियों के संदर्भ में अपना आंकलन प्रस्तुत करते हुए मुख्यमंत्रियों को चेतावनी दी कि वे आतंकवाद का सामना करने के लिए तैयार रहें, क्योंकि भविष्य में आर्थिक केन्द्रों, सैन्य ठिकानों, परमाणु प्रतिष्ठानों और विज्ञान केन्द्रों को आतंकी हमले का निशाना बनाया जा सकता है। उन्होंने राज्यों में खुफिया तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया और यह जरूरत भी बताई कि खुफिया सूचनाएं हासिल करने के लिए लोगों को पुलिस का मददगार बनाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री का ध्यान पुलिस बलों में रिक्तियों को भरने तथा उसकी कार्यदक्षता बढ़ाए जाने पर था। सम्मेलन में मुख्यमंत्रियों ने केन्द्र की ओर से अधिक सक्रिय दृष्टिकोण तथा राज्यों के बीच नीतियों में बेहतर समन्वय की अपेक्षा की। इसके अतिरिक्त राज्यों ने अधिक तादाद में त्वरित कार्यवाई बल बेहतर उपकरणों की भी मांग की। सम्मेलन में गृहमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रियों का एक समूह भी गठित किया गया, जो आतंकवाद से निपटने के तौर–तरीकों के संदर्भ में अपने सुझाव देगा।

यह सब निःसंदेह आवश्यक है , लेकिन यह विचित्र है कि आतंकवाद के मूल पक्ष तथा उसका सामना करने के उपायों का सम्मेलन में हुए विचार–विमर्श में शामिल नहीं किया गया। शायद इसका एक कारण यह है कि यह अधिकांश मुख्यमंत्रियों की सीमाओं से कहीं अधिक बड़ा विषय है। दरअसल आतंकवाद असहिष्णुता का अंतिम कदम है। यह तब उत्पन्न होता है जब कोई व्यक्ति यह समूह उस

पक्ष से बातचीत के सारे रास्ते अपनी और से बंद कर लेता है, जिससे उसके मतभेद हो इसके स्थान पर अपने प्रतिपक्षी को जड़ से समाप्त करने को अपना ध्येय बना लेता है। आतंकवाद उस सहिष्मुता का एकदम विरोधी पक्ष है जो कि लोकतंत्र का एक विशिष्ट गुण है। आतंकवादी ओर उग्रवादी हमारी पुलिस और सुरक्षा बलों के भ्रष्टाचार का लाभ उठाते है। एक जेहादी को बांग्लोदश से भारत घुसपैठ करने के लिए केवल पांच सौ रूपए की जरूरत होती है। यह कल्पना करना भी कठिन है कि भ्रष्टाचार के इस सागर में आतंकवाद रोधी पुलिस बल ईमानदारी का टापू साबित होगा। हम सभी इससे भली–भांति वाकिफ है कि किस तरह विस्फोटक हथियार संचार उपकरण, औरंगाबाद, हैदराबाद, मुम्बई, दिल्ली आदि दूर–दराज तक के क्षेत्रों में पहुँचाए गए। ज्यादातर आतंकी घटनाओं की नौबत इसलिए आती है, क्योंकि राज्यों में खुफिया नेटवर्क अस्त–व्यस्त तो होता ही है, पुलिस बटालियनों का प्रशिक्षण भी असंतोषजनक होता है। राज्यों ने इस सुझाव पर भी अमल नहीं किया कि पूर्व सैन्य कर्मियों को पुलिस बटालियनों में नियुक्त किया जाना चाहिए। इस सबके ऊपर उस कारण की अनदेखी की जा रही है जिसने आतंकवाद का दायरा विस्तृत बनाया है और यह कारण है–कुशासन।

बेशक प्रधानमंत्री ने जो कदम बताए है वे महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जब तक राजनीतिक वर्ग अपने तंत्र को साफ–सुधरा बनाने के लिए नहीं प्रस्तुत होता और हमारे लोकतंत्र में अनुशासन और सहिष्णुता के गुणों का समावेश नहीं किया जाता तब तक किसी विशेष सुधार की उम्मीद करना व्यर्थ ही है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

आतंकवाद, चुनौती और संघर्ष–मनोहर लाल बाघम, शिवचरण विश्वकर्मा।
रिलेशनशिप बिटविन इन्टरनेशनल टैरेरिज्म स्टेट टैरर एण्ड हयूमन राईट्स इन वर्ल्ड आर्डर (निबन्ध) इण्डियन सोसायटी आफ इन्टरनेशनल लॉ के 29 वें अधिवेशन 1987 में प्रस्तुत–पे.एन. सक्सेना।
आई. बेलिशनोव व एन.जेडनोव, टेरेरिज्म एण्ड इन्टरनेशनल लॉ, 1984, पृष्ठ–25।
जी.आई. टुनकिन, इण्टरनेशनल लॉ, 1982, पृष्ठ–22।
अरूण शौरी–पाकिस्तान–बांग्लादेश, आतंकवाद के पोषक।
हिन्दुस्तान टाइम्स, 10 सितम्बर, 2006।
इण्डिया टूडे, 3 मार्च 2010।
उपरोक्त वही।
इण्डिया टूडे, 3 अगस्त 2011।
दैनिक जागरण, 11 सितम्बर 2006।